भारत–नेपाल सम्बन्ध

डॉ0 प्रदीप कुमार सिंह*
राज लक्ष्मी सिंह**

नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्धों की जड़े अत्यन्त गहरी है। नेपाल ही एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है, जिसके साथ भारत ने वीजा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। दोनों देशों के बीच बिना बीजा के ही नागरिक आ जा सकते है। भारत के उत्तर में स्थित नेपाल एक भूमि घेरित (Land Pocked) देश है। भारत–नेपाल सीमा रेखा 1850 किलोमीटर लम्बी है। भारत के लिए नेपाल की स्थिति सामरिक महत्व की है, क्योंकि नेपाल दो बड़े देशों भारत तथा चीन के बीच एक मध्यस्थ राज्य (Buffen State) के रूप में स्थित है।

राजनीतिक सम्बन्धों के स्तर पर भले ही दोनों देशों के बीच अनिश्चितता का वातावरण विद्यमान है, लेकिन आर्थिक सम्बन्धों में दोनों देशों के बीच संतोषजनक विकास हो रहा है। दोनों देशों के आर्थिक सम्बन्धों में मुख्य रूप से व्यापार तथा निवेश, विकास सहायता, मानव संसाधन विकास तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग सम्मिलित है। भारत–नेपाल के साथ विकास में जो साझेदारी कर रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू मानव संसाधन विकास है। इसके द्वारा भारत नेपाल में प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा शिक्षा के कई कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। भारत नेपाली सेना को वर्तमान में प्रशिक्षण की सुविधा दे रहा है तथा प्रतिवर्ष नेपाल के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्ती हेतु 1800 स्कॉलरशिप दे रहा है। नेपाल जल विद्युत स्रोतों से सम्पन्न देश है, सरकारी अनुमान के अनुसार नेपाल में 43000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता विद्यमान है, लेकिन अभी तक इस क्षमता का सही दोहन नहीं हो पाया है इसके बावजूद भारत ने नेपाल में दोनों देशों के पारस्परिक लाभ की कई महत्वपूर्ण संयुक्त जल विद्युत परियोजनाओं को अंजाम दिया इनमें देवी घाट, त्रिशुल, करनाली तथा पंचेश्वर जल विद्युत परियोजनाएं प्रमुख है। दोनों देश इस क्षेत्र में सहयोग के महत्व को समझते है। इस क्षेत्र में (ऊर्जा तथा जल संसाधन) सहयोग के लिए 2008 में दोनों देशों ने एक त्रिस्तरीय सहयोग की व्यवस्था को लागू किया है। मंत्री स्तर, सचिव स्तर तथा तकनीक विशेषज्ञों–तीनों स्तरों पर निरन्तर विचार–विमर्श व सहयोग हेतु आयोग और कमेटियों का गठन किया गया है। भारत वर्तमान में ऊर्जा सुरक्षा हेतु ऊर्जा के नए क्षेत्रों को तलाश रहा है, इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में वह नेपाल के साथ सहयोग हेतु उत्सुक है। अगर भारत को अपनी वर्तमान आर्थिक गति को बनाए रखना है, तो उसे भविष्य में विदेशों में ऊर्जा के नए स्रोतों का सहारा लेना पड़ेगा तथा नेपाल भी अपने तीव्र आर्थिक विकास के लिए अपने जल संसाधनों तथा ऊर्जा क्षेत्र का विकास करना चाहता है। इसलिए इसे क्षेत्र में दोनों के सहयोग की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। भारत और नेपाल के बीच एक लम्बी खुली सीमा है, इसलिए नागरिकों को आने–जाने के लिए वीजा की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ वर्षों से सीमा रेखा पर आतंकवादियों के प्रवेश, वस्तुओं की तस्करी तथा नकली भारतीय मुद्रा के अवैध आयात की घटनाएं होने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए दोनों देशों ने तय किया कि वे इन क्षेत्रों में प्रभावी संचार सुविधाओं का विकास करेंगे तथा सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं का भी विकास करेगा।

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, के0एस0 साकेत पी0जी0 कालेज, फैजाबाद
** शोध छात्रा, के0एस0 साकेत पी0जी0 कालेज, फैजाबाद

पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सहयेाग को बढ़ावा दिया है, प्राचीन काल से ही दोनों के बीच सांस्कृतिक सहयोग है। इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आतंकी संगठन लश्कर–ए तैयबा व पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी (आई0एस0आई0) के लिए सुरक्षित ठिकाना बन रहे। नेपाल की सरजमीं से भारत की सुरक्षा के लिए खतरे का मुद्दा भी इसमें शामिल है। प्रत्यर्पण संधि व पारस्परिक कानूनी सहायता के समझौते की आवश्यकता पर भारत ने बल दिया।

भारत और नेपाल के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों का तीव्र विकास हो रहा है लेकिन राजनीतिक सम्बन्धों को ठोस आधार तभी प्राप्त हो सकेगा जब नेपाल में राजनीतिक स्थिरता स्थापित हो जाएगी तथा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया गतिशील हो जाती है। इसलिए राजनीतिक मामलों में दोनों के बीच अभी भी अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। **नेपाल में 1990 से 2000** तक का दौर आंतरिक राजनीति में उथल पुथल व माओवादी हिंसा से भरा रहा । इस दौरान 12,500 से अधिक नागरिकों को जान से हाथ धोना पड़ा । नेपाल में आंतरिक आपातकाल भी लागू किया गया और इसी उथल पुथल के दौर में 26 अप्रैल 2006 को संसद बहाली की घोषणा हुई। आंतरिक अशातिं के दौर मं आलोचकों का मानना था कि भारतीय नीति ढुल–मुल रही, इस कारण वहां के राजनीतिज्ञ भारत के प्रति उत्साहित नहीं दिखे। अप्रैल 2006 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को इतना श्रेय अवश्य दिया जा सकता है विशेष दूत के रूप में डॉ0 कर्ण सिंह की नेपाल यात्रा हुई तथा उन्होंने नेपाल के महाराजा के साथ मिलकर कुछ रास्ता अवश्य निकाला था। भविष्य में नेपाल में राजनीतिक स्थिरता सबसे बड़ी चुनौती होगी। नई सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसें संबध रखना चाहेगी। क्योंकि माओवादी तथा साम्यवादी दल अवश्य चाहेगें कि चीन को नेपाल के साथ रिश्तों में पर्याप्त स्थान मिले।नेपाल के राजनेता भारत – नेपाल की 1950 की शांति व मैत्री संधि की समीक्षा की निरंतर मांग करते रहे है। सितंबर 2008 के भारत यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड ने भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और भारत सरकार ने नेपाल में शांतिमय लोकतांत्रिक संक्रमण के लिए सहायता का वचन दिया, तुरंत राहत के लिए 20 करोड़ रूपये की घोषणा की तथा भारत नेपाल को 150 करोड़ रूपये उधार के रूप में देगा। इसके पश्चात नेपाल में राजनीतिक संकट चलता रहा और माधव कुमार नए प्रधानमंत्री बने। उनका भी दृष्टिकोण पूर्व की भांति रहा। जहां तक भारत सरकार की बात आती है तो हमारा यह प्रयास रहा है कि भारत के नेपाल के साथ सम्बन्धों को एक नवीन गतिशीलता प्रदान की जाए, जिससे दोनों देशो के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के पारस्परिक हितों को सुदृढ़ किया जाए। इसी दौरान नेपाल में 28 अगस्त 2011 को बाबूराम भट्टाराई प्रधानमंत्री बने, उनका भी दृष्टिकोण पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रीयों जैसे ही है।

2014 में भारत में केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के साथ नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने। नरेन्द्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क राज्यप्रमुखों को बुलाकर यह सिद्व कर दिया कि पड़ोसी राज्यों से मित्रता चाहते है, वे उनको अधिक प्राथमिकता देते है। सबका साथ, सबका विकास का नारा लेकर चलने वाले भारतीयों प्रधानमंत्री ने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके प्रयासों से **23** वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा के बाद **26** जुलाई **2014 को भारत** व नेपाल **संयुक्त आयोग की बैठक सम्पन्न** हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इस संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तथा महेन्द्र बहादुर पाण्डे ने की। इस बैठक में सुरक्षा व्यापार निवेश तथा जल संसाधन से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा हुई। 3 से 4 अगस्त 2014 को पड़ोसी

राज्यों को प्राथमिकता देते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल यात्रा के माध्यम से नेपाल के साथ संबंध बेहतर बनाने की दिशा में बेहतरीन प्रयास किया।नेपाल में लगभग 17 वर्ष के लम्बे **इंतजार** के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है, उनसे पहले इन्द्रकुमार गुजराल नेपाल गये थे। नेपाल मे प्रधानमंत्री का गर्म जोशी से स्वागत किया गया नेपाल के प्रधान मंत्री सुशील कुमार कोइराला ने प्रोटोकाल तोड़कर भारतीय प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। ऐसा पहली बार हुआ कि जब कोई शासनाध्यक्ष, दुसरे शासनाध्यक्ष की अगवानी के लिए स्वयं हवाई अड्डे पर पहुंचा हो।

भारतीय प्रधानमंत्री ने उस नेपाली मान्यता का पुरजोर खण्डन किया कि भारत उसकी संप्रभुता का सम्मान नही करता, उनके मामलों में हस्तक्षेप करता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल जो भी विकास का मार्ग स्वयं निर्धारित करेगा, वो जो भी दिशा तय करेगा, भारत उसमें सहयोगी बनेगा। वे नेपाल के आंतरिक मामलों में कोई भी झुकाव दिखाने से बचे रहे। उन्होंने माओवादियों की भी अप्रत्यक्ष सराहना करते हुए कहा कि उन्होंनें शस्त्र को छोड़कर शास्त्र के सहारे समाज को बदलने का रास्ता अपनाया, युद्व को छोड़कर बद्ध को अपनाया।

प्रधानमंत्री ने नवीन संविधान लागू कर राजनीति के संघीय, लोकतांत्रिक , राजतांत्रिक ढाचें को संस्थागत बनाने के उनके प्रयासों में सहयोग देने की बात कही और कहा कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगें।

भारत–नेपाल ने सीमाओं को सुरक्षित करने तथा खुली सीमा का उपयोग एक दूसरे की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले अनैतिक तत्वों को न करने देने का संकल्प लिया है। सीमा से जुड़े विवादों को वार्ता के माध्यम से हल करने हेतु सहमति बनाई गई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूदीन ने कहा कि प्रधानमंत्री फोर सी एजेंडें के साथ नेपाल गये थे। फोर सी अर्थात कॉपरेशन (सहयोग), कल्चर (संस्कृति) , कनेक्टिविटी (संयोजकता) और कॉन्सीटीटयूशन (संविधान)। भारत व नेपाल के प्रधानमंत्रीयों की संयुक्त बैठक में विभिन्न मुदों पर सहमति बनी। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर आस्था व विश्वास का अद्वितीय केन्द्र है। भारतीय प्रधानमंत्री ने हिन्दू विधि से पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की तथा मन्दिर के संरक्षण हेतु 25 करोड़ रूपये राशि की सहायता की घोषणा की। मोदी की पशुपतिनाथ यात्रा सांस्कृतिक तथा धार्मिक एकता को इंगित करती है। इस यात्रा ने कूटनीति के क्षेत्र में आए अंतराल को भरने की एक ईमानदार कोशिश की है।

राजनयिक यात्राओं, शासनाध्यक्षों की यात्राओं आदि से सकारात्मक माहौल अवश्य बनता है। यहाँ से डाकघर सभी तथ्यों के बावजूद यह मानना जल्दबाजी होगी कि भारत –नेपाल में सभी मतभेद दूर हो गयें है, और मैत्री व सहयोग के संबंध स्थायी बने रहेंगें। नेपाल–भारत मैत्री संधि, शांति क्षेत्र घोषित करनें, तस्करी की समस्या, जन संसाधनों का बंटवारा, नेपाली परियोजनाओं में भारत की हिस्सेदारी जैसे अनेक मामले है, जिन पर अभी काफी काम किया जाना शेष है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए भारत को भी अब यह स्वीकार कर लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि नेपाल अब वयस्क हो चुका है, अतः उसे अंगुली पकड़कर राह दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ नेपाल को भी यह समझना होगा कि हर प्रकार से संरक्षण देने वाला भारत अपने विरूद्व किसी भी बात को सहन नहीं करेगा। शायद इसी सोच में ही दोनों राष्ट्रों के मध्य आने वाले तनावों व मतभेदों का निराकरण हो सकता है।

संदर्भ व टिप्पणियाँ :–

1. पुष्पेश पंत व श्रीपाल जैनः अंतरराष्ट्रीय संबंध, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ 2006
2. डा0 मुनेष कुमारः स्वतंत्र भारत की विदेश नीति, डिस्कवरी पब्लिशिगं हाऊस, प्रा0लि0, नई दिल्ली, 2010
3. वर्ल्ड फोकस, अप्रैल 2011
4. वर्ल्ड फोकस, सितम्बर 2011
5. वर्ल्ड फोकस, नवम्बर व दिसम्बर, 2011
6. संपादकीय पत्रिका, 5 अगस्त 2014
7. राजस्थान पत्रिका, 17 जून 2014
8. दैनिक भास्कर, 5 अगस्त 2014
9. दैनिक भास्कर, 4 अगस्त 2014
10. वर्ल्ड फोकस अक्टूबर 2014

●